

की पूर्ति होगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के इंट्रोडक्शन का घोर विरोध करता हूँ।

DR. TRIGUNA SEN: Sir, in the Statement of Objects and Reasons we have mentioned that it is only to cover a limited scope. The rate of royalty was decided upon by the award of the late Prime Minister in 1962. Later on the Prime Minister gave the award the other day to enhance the rate of royalty with retrospective effect. So unless this is amended we cannot pay this with retrospective effect. Therefore, this Bill has got a very restricted scope.

Mr. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Oil-fields (Regulation and Development) Act, 1948."

The motion was adopted.

Dr. TRIGUNA SEN; Sir, I introduce the Bill.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, AND SHIPPING & TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Shri Chand Goyal, Shri Banerjee and Shri Fernandes have written to me that they want to oppose the introduction of this Bill. At the introduction stage they can only make a very brief submission.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): Sir, I wish to oppose this Bill, the Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill. Sir, if this particular

Bill is passed...(Interruption). Sir, I want your undivided attention.

The question is that this particular Bill has been brought forward after repeated objections by the C. P. I., S. S. P. and other parties also. They have relentlessly opposed this provision on the ground that if this Government cannot give a need-based minimum wage to their employees or to increase their wages, how can the Members of Parliament who are the representatives of the poor people raise their salaries or their allowance from Rs. 31 to Rs. 51 per day? Our moral objection is that this particular provision is at the cost of the country. I would request the hon. Prime Minister who is the Finance Minister also to explain to the House the urgent need of raising the allowance of the Members of Parliament. When the amount was raised from Rs. 21 to Rs. 31 per day, then also there was an objection raised by us. At this hour, when a decision has been taken by the Cabinet that no wage increase should be there for the Government employees, I would request the Minister of Parliamentary Affairs to withdraw the Bill.

14.47 hrs.

[SHRI GADILINGANA GOWD *in the Chair*]

SHRI VIKRAM CHAND MAHAJAN (Chamba): On a point of order, Sir. Before a Member opposes the Bill, he should make a statement in the House that if the Bill is passed, he will not receive the enhanced allowance.

SHRI RABI RAY (Puri): Quite irrelevant.

SHRI S. M. BANERJEE: I appreciate the sense of humour which is very crude.

The question at present is, when we are nationalising the banks for resources, when we are trying to implement various plans and specially, when 21 lakh Central Government employees and an equal number of State Government employees have been asked to tighten their belts' and not to ask for any

* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 21-7-69.

[Shri S.M. Banerjee]

wage increase, and when movements after movements have been completely crushed by bullets by the same Government saying that they have no money pay, at this hour, can the Members of Parliament who are the representatives of the poor people raise their salaries or allowance from Rs. 31 to Rs. 51 per day? With all the concessions mentioned in the Bill, the increase will be to the tune of Rs. 1000 per month. All the Members of this House, whether belonging to this side or to that side should realise that it is at the cost of the other people. I am really sorry that after hearing the speech of the Prime Minister, they still want their salaries to be increased at the cost of the people. I only plead and request you, Sir, to kindly ask the Minister of Parliamentary Affairs to withdraw the Bill.

श्री श्रीचन्व गोयल (चण्डीगढ़): सभापति महोदय, आप को स्मरण होगा कि दोनों सदनों की एक समिति बनी थी जिसने इस विषय पर विचार किया था कि संसद के सदस्यों को अपना कर्त्तव्य निभाने में सुविधा हो, उस दृष्टि से विचार किया जाय। उस समिति ने दो प्रकार के सुझाव दिये। कुछ सुझाव सर्वसम्मत सुझाव थे, कुछ सुझाव बहुमत से दिए गए थे। जो सुझाव बहुमत से दिए गए थे मैं उनकी चर्चा नहीं करना चाहता। यह एलाबेंस 31 रुपये से 51 रुपये बढ़ाने का जो सुझाव था वह बहुमत से दिया गया था, सर्वसम्मति से नहीं दिया गया था। सर्वसम्मति सुझाव तीन थे। उनमें से एक यह था कि संसद का एक सदस्य अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में, तथा अपने राज्य में अपने कर्त्तव्य का पालन प्रभावी ढंग से कर सके इस दृष्टि से उसको यातायात की सुविधा मिलनी चाहिए और उसके लिए अपने राज्य के अन्दर फ्री पास बस का दिया जाय ताकि उसको अपने कर्त्तव्य का निर्वाहन करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। दूसरी एक बात पर और विचार किया गया कि जो सैकड़ों की संख्या में सदस्यों के पास पत्र आते हैं देश के कोने-कोने से, उनका उत्तर देने में जो डाक का व्यय होता है उसके बारे में भी संसद सदस्यों को विचार करना पड़ता है और कई बार उत्तर देने में जो डाक

का व्यय होता है उस के बारे में भी संसद सदस्यों को विचार करना पड़ता है और कई बार उत्तर देने में इस कारण संकोच होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति उस को इस बात की आज्ञा नहीं देती। इस कारण से समिति ने यह सर्वसम्मति सुझाव दिया था कि सब सदस्यों को 100 रु० तक जितना भी वह खर्च करें इसके लिए दिया जाय। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को सविस स्टाम्प मिलते हैं उस मात्रा में सविस स्टाम्पस एक संसद सदस्य को दिए जायें तो उसमें उनको सुविधा होगी। तीसरी समस्या स्टेनोग्राफर की है। कम से कम मैं व्यक्तिगत रूप से इस कठिनाई को बहुत अनुभव करता हूँ कि जब तक स्टेनोग्राफर की सुविधा एक संसद सदस्य को न मिले तब तक पत्र-व्यवहार करने में उसे बड़ी कठिनाई होती है..... (व्यवधान) उस में सबसे बड़ा एक ही सुझाव था कि सदस्यों को स्टेनोग्राफर की सुविधा जरूर मिलनी चाहिए ताकि जो कुछ पत्र-व्यवहार करना होता है वह आसानी से हो सके। आज हम देख रहे हैं कि उन सब सुविधाओं का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उनकी चर्चा ही नहीं है। आखिर उद्देश्य इसका यह है कि संसद का हरेक सदस्य अपनी जिम्मेदारी को निभा सके, अपने कर्त्तव्य का पालन कर सके, एक संसद सदस्य के नाते जो उत्तरदायित्व उसके ऊपर डाला गया है उसका वह पालन कर सके, इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की थी कि उसको सुविधाएं मिलती रहें। लेकिन आज 31 रुपये से 51 रुपया एलाबेंस बढ़ाने जा रहे हैं क्योंकि यह अधिकार हमारे हाथ में है देश की जनता और समाचार पत्र अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चूंकि यह उनके अधिकार की बात थी इसलिए उन्होंने अपने लिए एलाबेंस में वृद्धि कर ली। बाकी और जिन लोगों की आवश्यकता है उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस चर्चा से, लोगों को इस प्रकार की क्रिटिसिज्म से हम बच सकें इसके लिए बजाय दैनिक भत्ते में वृद्धि करने की सुविधाओं के

ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाय क्योंकि सुविधाएं बुनियादी चीजें हैं। हमारा जो कर्तव्य है संसद सदस्य के नाते देश के प्रति, अपने चुनाव क्षेत्र के प्रति, अपने राज्य के प्रति उसका हम पालन कर सकें, इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि भत्ते में वृद्धि करने के बजाय सुविधाएं प्रदान करने वाला विधेयक यहां पर आना चाहिए था। इस-लिए मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री जार्ज फरेन्डलीख (बम्बई दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ अभी कुछ ही देर के पहले प्रधान मंत्री जी ने अपना बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के समर्थन में एक बयान पेश किया और अब यह विधेयक यहां आ रहा है जिसके जरिए साल में लगभग 1 करोड़ रुपया इस संसद में बैठने वाले लोगों को देने की व्यवस्था हो रही है। इसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था की जा रही है कि चूँकि इस विधेयक के संबंध में एक बयान मंत्री महोदय ने इस सदन में पिछले सत्र के अन्तिम दिवस दिया था इसलिए इस विधेयक से जो भी आर्थिक फायदा एक संसद सदस्य को होगा वह 1969 से लागू किया जायगा। एक तरफ नई आर्थिक दिशाओं की बात प्रधान मंत्री के मुँह से आना और अर्थ मंत्री बनने के बाद पहले ही दिन इस सदन के अन्दर एक करोड़ रुपये का एक अलग ही दिशा देने वाला काम करना कहां तक इस सरकार को शोभा देता है, यह मैं नहीं समझ सकता हूँ। पिछले कई वर्षों से इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि इस सदन में बैठने वाले लोग भले ही कोई बहुत बड़ा मकसद ले कर आते हों लेकिन जनता की आशाएं और आकांक्षाएं रहती हैं अपनी जगह पर और अपने निजी स्वार्थों का हिसाब किस तरह से पूरा किया जा सकता है इस बात को प्राथमिकता दी जाती है। बरना इसी सदन में पिछले सत्र में जब पेंशनर लोगों के मामले को हम लोगों ने उठाया और दो वर्षों से उठा रहे हैं, हर एक अर्थ मंत्री के मुँह से या उनके जो भी डिप्टी मंत्री रहते हैं उनके मुँह से यह बात आई कि आर्थिक तकलीफ के कारण हम पेंशनर की तनखाह बढ़ाने का काम नहीं कर सकते हैं। मुझे पूछना है

अध्यक्ष महोदय, कि जहां पेंशनर महीने में 15 और 18 रुपये लेकर जिन्दगी बसर करते हैं वहां उन के पेंशन में 5 और 10 रुपये वृद्धि करने की बात आती है तो आपको आर्थिक कठिनाई महसूस होती है तो संसद के सदस्य के भत्ते में 30 रुपये की बढ़ाती देने में आपको आर्थिक कठिनाई नहीं महसूस होती है?... (व्यवधान) जरूरत हो या न हो यह बेमतलब की बात है। आपकी नीतियों और आपके कामों में एकरूपता नहीं है। आपके सोचने में एक दिशा नहीं है। आपकी खुद की जहां बात आती है तब आर्थिक कठिनाई आपको नहीं महसूस होती है। जब पेंशनर का मामला आता है सरकारी कर्मचारियों का मामला आता है तब आपको आर्थिक कठिनाई दिखाई देती है। अपने सोचने में, अपने दिमाग में, अपने व्यवहार में जो दो जवान से आप लोग अपना काम चला रहे हो इसका यह एक सबूत मैं आपके सामने रख रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि इस विधेयक को किसी भी हालत में इस सदन में पेश न करने दिया जाय और आप मंत्री महोदय से कहें कि इस सदन की यह राय है कि संसद के सदस्यों को अच्छे ढंग से अपने कर्तव्य को निभाने के लिए किन्हीं सुविधाओं की आवश्यकता हो तो वह सुविधाएं उनको दीजिए लेकिन रुपया बढ़ा कर उनका ऐशोआराम बढ़ाने का जो यह तरीका है उसको तो बिल्कुल यहां पर रोका जाय।

श्री मधुलिमये (मुंगेर) : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। आपको याद होगा कि जब यह मामला पिछली बार सदन में आया था...

MR. CHAIRMAN: I want to hear, your point of order. I do not want to hear all these.

श्री मधु लिमये : आप प्वाइंट आफ आर्डर नहीं सुनेंगे? मैं प्वाइंट आफ आर्डर पर बोल रहा हूँ। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ।

MR. CHAIRMAN: In the name of point of order, I do not want to hear all these..... (Interruptions).

श्री मधु लिमये : पहले आप सुन लीजिए... (व्यवधान)... आप अपने शब्दों को वापस लीजिए... (व्यवधान)... मेरी बात सुने बगैर यह कैसे कह सकते हैं ?

MR. CHAIRMAN : Under which rule you are raising it ?

श्री रवि राय : पहले आप सुन लीजिए ।

श्री मधु लिमये : अगर आप हिन्दी नहीं समझ सकते हैं तो आप ट्रांसलेशन के लिए कान में मशीन लगा लीजिए... (व्यवधान)... प्वाइंट आफ आर्डर कैसे नहीं सुनेंगे ?

MR. CHAIRMAN : If you want to raise other issues, you have to give notice.

SHRI RANDHIR SINGH (Rohtak) : That must be expunged.

MR. CHAIRMAN : Under which rule you are raising it ?

श्री मधु लिमये : 376 में है । यहाँ पर इस विषय पर रूलिंग हो चुकी है... (व्यवधान)... ट्रांसलेशन वाला लगाइए अगर आप हिन्दी नहीं समझते हैं... (व्यवधान)...

SHRI RANDHIR SINGH : On a point of order, Sir. He has said something against the Chair. That should be expunged or he must withdraw it.

15 hrs.

श्री मधु लिमये : मैं एक ही वाक्य में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ । अध्यक्ष महोदय ने इसके बारे में रूलिंग दी हुई है कि जो सर्व-सम्मत फैसले होंगे, उन्हीं को बिल की शकल में कार्यान्वित किया जायगा । आप तो चैयरमैन हैं, लेकिन इस विषय में अध्यक्ष महोदय का निर्णय आ चुका है... (व्यवधान)... स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ यहाँ पर कोई कानून नहीं आ सकता, जब तक स्पीकर के रूलिंग को बदला नहीं जाता है । इसलिए यह बिल यहाँ पर इन्ट्रोड्यूस नहीं हो सकता है, जब तक स्पीकर का निर्णय यहाँ पर है । आप उसको बदलिये । यही मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

SHRI RANDHIR SINGH : You can give your own ruling. Why should the Chair be denigrated ? My hon. friends can vote against the Bill if they want.

SHRI UMANATH (Pudukkottein) : On a point of order. I object to the introduction of this Bill because it contains provisions which are violative of a certain mandate given by this very House on this question.....

AN HON. MEMBER : When ?

SHRI UMANATH : That is my point of order. This Bill contains provisions for increasing the salary.....

MR. CHAIRMAN : I am not going to allow anybody now.....

SHRI MADHU LIMAYE : Who are you ?

SHRI UMANATH : If you are not going to allow our point of order, we are not going to allow you also.....

SHRI MADHU LIMAYE : Who are you
You are not the Speaker.

SHRI C. C. DESAI (Sabar Kantha) : He is the Speaker for all purposes. He is the Chairman, and he has the powers of the Speaker.

SHRI UMANATH : If you are not going to allow us in this arbitrary manner, we are not going to allow you also.

I have said that this Bill is violative of the mandate given by this Bill. Government cannot bring forward a Bill which is violative of the mandate of the House. I shall tell you what this mandate has been.

श्री मधुलिमये : आप इस तरह से नहीं चला सकते ।

MR. CHAIRMAN : I am not allowing.

SHRI MADHU LIMAYE : Who are you ?

MR. CHAIRMAN : Let him not talk like that. I am the chairman. He should withdraw those words. I am the chairman here.

SHRI UMANATH : We should not allow you if you are not going to allow us.

MR. CHAIRMAN : I am the Chairman here. The hon. Member should resume his seat.

SHRI MADHU LIMAYE : On a point of order, how can you refuse to listen to us ? I am going according to the rules.

SHRI UMANATH : I am on a point of order.....

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Under what rule is he raising the point of order ?

SHRI MADHU LIMAYE : He is not the speaker.....

MR. CHAIRMAN : I am the Speaker as long as I am in the Chair.

SHRI RAINDHIR SINGH : He must apologise to the Chair. He must apologise. The Chair cannot be addressed by saying 'Who are you ?' That is very bad. He must apologise. I shall not resume my seat until he apologises.

AN HON. MEMBER : Who are you ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : (बलरामपुर) सभापति महोदय, आप इस समय अध्यक्ष की पीठ पर विराजमान हैं, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान हमें करना भी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस सदन के सभी सदस्य जो भी इस पीठ पर बैठा हो, उसका सम्मान करेगा। लेकिन मेरा निवेदन कि आप इस विषय पर सँभरों को बोलने का मौका दें क्योंकि यह विषय सदस्यों से सम्बन्धित है। लम्बा भाषण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दो-चार सदस्य बोलना चाहते हैं तो आप उनको बोलने दीजिए—यही मेरी प्रार्थना है।

MR. CHAIRMAN : I have not said that I shall not hear anybody. But I have to follow certain rules. I have not said what the hon. Member has said. But I have to observe certain rules and regulations here. Supposing everyone of the five hundred odd Members want to speak, how is it possible ?

so, we have been following the procedure* that such of those Members as have given notice should be allowed to speak. Otherwise, I shall have to call everyone of the five hundred odd Members, and if I do that, then the whole day will be utilised for that purpose. So, I am adhering to the rules and regulations and I am not allowing anybody who has not given notice to me. Therefore I should not be misunderstood if I do not call every Member who rises.

SHRI UMANATH : we are not making speeches. I am only raising a point of order.

SHRI MADHU LIMAYE : No Bill can be introduced against the ruling of the speaker.

MR. CHAIRMAN : What is the point of order of Shri Umanath ?

SHRI UMANATH : I shall confine myself to the point of order.

SHRI RANDHIR SINGH : What about the derogatory remarks ?

SHRI UMANATH : My point is that this Bill is violative of the mandate of this House. It is on that point that I am making my submissions.

SHRI RANDHIR SINGH : First, he must withdraw those remarks.

MR. CHAIRMAN : Let Shri Randhir Singh resume his seat now.

SHRI RANDHIR SINGH : I cannot bear any insult to the Kisan Chairman. He should not be insulted. I shall not allow to him to speak until he apologises.

SHRI UMANATH : Let us keep on standing. I am not bothered. Even if it be seven o' clock, let us keep on standing together.....

SHRI RANDHIR SINGH : Those remarks should be expunged.

SHRI UMANATH : I am not making a speech. I am only raising a point of order. This Bill has been brought forward on the basis of certain recommendations of a committee which was set up in pursuance of

[Shri Umanath]

a resolution of this House. At the time of the passing of that resolution, it contained reference to many matters including increase in salary. A specific question was asked of the Speaker whether that resolution referred to facilities or salaries. The hon. Speaker is on record that it is only limited to facilities and not to salaries. But now this Bill contains provisions with regard to salaries.

In the committee, some Member raised the question of salary revision. Again, the question came up whether the committee had a right to go into the salary revision. It was again referred by the committee to the Speaker to ascertain whether the committee had that right.

MR. CHAIRMAN: what is the point of order ?

SHRI UMANATH: The point of order is that it is violative of the mandate of the House. The question was referred to the Speaker whether the committee had got any right to go into the question of salaries. The Speaker gave his ruling to the commi-

tee in writing that the committee had the right to go only into question of facilities and not into the question of salaries,

We find that the committee has violated the ruling of the Speaker given subsequently. So, this Bill is based on a position which is violative of the Speaker's ruling as well as the mandate of this House. That is why I object to the introduction of the Bill.

MR. CHAIRMAN: I was also in that committee, and I know that this point was discussed in the committee, and it came to a decision that it was a joint committee consisting of Members from both Lok Sabha and Rajya Sabha and, therefore, the Speaker's ruling would not come in the way of their suggestions.

The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954".

The Lok Sabha divided:

Division No. 1]

AYES

[15.13 hrs.

Achal Singh, Shri
Agadi, Shri S. A.
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Ahmed, Shri F. A.
Ahmed, Shri J.
Amat, Shri D.
Amin, Shri R. K.
Amin, Shri Ramchandra J.
Asghar Husain, Shri
Azad, Shri Bhagwat Jha
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barua, Shri R.
Baswant, Shri
Besra, Shri S. C.
Bhagat, Shri B. R.
Bhagavati, Shri
Bhandare, Shri R. D.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B. N.
Birua, Shri Kolai
Bist, Shri J. B. S.
Bohra, Shri Onkarlal
Burman, Shri Kirit Bikram
Deb

Buta Singh, Shri
Chanda, Shri Anil K.
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrika Prasad, Shri
Chaturvedi, Shri R. L.
Chavan, Shri D. R.
Choudhary, Shri Valmiki
Choudhury, Shri J. K.
Dalbir Singh, Shri
Damani, Shri S. R.
Dar, Shri Abdul Ghani
Dasappa, Shri Tulsidas
Dass, Shri C.
Deoghare, Shri N. R.
Deshmukh, Shri B. D.
Deshmukh, Shri K. G.
Deshmukh, Shri Shivajirao S.
Dhillon, Shri G. S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Digvijai Nath, Shri Mahant
Dinesh Singh, Shri
Dixit, Shri G. C.
Dwivedy, Shri Nageshwar
Ering, Shri D.

Gajraj Singh Rao, Shri
Gandhi, Shrimati Indira
Ganesh, Shri K. R.
Ganga Devi, Shrimati
Gautam, Shri C. D.
Ghosh, Shri Bimalkanti
Ghosh, Shri P. K.
Ghosh, Shri Parimal
Girja Kumari, Shrimati
Gudadinni, Shri B. K.
Gupta, Shri Ram Kishan
Hazarika, Shri J. N.
Hem Raj, Shri
Iqbal Singh, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Jadhav, Shri V. N.
Jamna Lal, Shri
Jena, Shri D. D.
Kahandole, Shri Z. M.
Kamble, Shri
Kamala Kumari, Shrimati
Karan Singh, Dr.
Kasture, Shri A. S.
Katham, Shri B. N.

Kavade, Shri B. R.
 Kedaria, Shri C. M.
 Kesri, Shri, Sitaram
 Khan, Shri M. A.
 Khan, Shri Zulfiqar Ali
 Kripalani, Shrimati Sucheta
 Krishna, Shri M. R.
 Kunte, Shri Dattatraya
 Kureel, Shri B. N.
 Kushwah, Shri Y. S.
 Laskar, Shri N. R.
 Lobo Prabhu, Shri
 Mahadeva Prasad, Dr.
 Mahadevappa, Shri Rampur
 Mahajan, Shri Vikram Chand
 Maharaj Singh, Shri
 Mahida, Shri Narendra
 Singh
 Mahishi, Dr. Sarojini
 Malhotra, Shri Inder J.
 Mandal, Shri B. P.
 Mandal, Dr. P.
 Mandal, Shri Yamuna Prasad
 Mane, Shri Shankarrao
 Marandi, Shri
 Master, Shri Bhola Nath
 Masuriya Din, Shri
 Mehta, Shri P. M.
 Menon, Shri Govinda
 Minimata Agam Dass Guru,
 Shrimati
 Mishra, Shri Bibhuti
 Mishra, Shri G. S.
 Mohamed Imam, Shri J.
 Mohammad Yusuf, Shri
 Mohsin, Shri
 Mrityunjay Prasad, Shri
 Mukerjee, Shrimati Sharda
 Murti, Shri M. S.
 Muthusami, Shri C.
 Naghnoor, Shri M. N.
 Naidu, Shri Chengalraya
 Naik, Shri G. C.
 Naik, Shri R. V.
 Nayar, Dr. Sushila
 Oraon, Shri Kartik
 Padmavati Devi, Shrimati
 Pahadia, Shri Jagannath
 Palchoudhuri, Shrimati Ila
 Pandey, Shri K. N.
 Pandey, Shri Vishwa Nath

Pant, Shri K. C.
 Paokai Haokip, Shri
 Parmar, Shri Bhaljibhai
 Parmar, Shri D. R.
 Partap Singh, Shri
 Parthasarathy, Shri
 Patel, Shri Manubhai
 Patil, Shri Anantra
 Patil, Shri C. A.
 Patil, Shri S. B.
 Patil, S. D.
 Patil, Shri T. A.
 Pramanik, Shri J. N.
 Qureshi, Shri Mohd Shaffi
 Radhabai, Shrimati B.
 Raghu Ramaiah, Shri
 Raj Deo Singh, Shri
 Rajni Devi, Shrimati
 Raju, Shri D. B.
 Ram, Shri T.
 Ram Dhan, Shri
 Ram Dhani Das, Shri
 Ram Sewak, Shri Choudhary
 Ram Subhag Singh, Dr.
 Ram Swarup, Shri
 Ramamoorthy, Shri S. P.
 Ramshekhar Prasad Singh,
 Shri
 Rana, Shri M. B.
 Randhir Singh, Shri
 Rane, Shri
 Rao, Shri Jaganath
 Rao, Shri Mthyal
 Rao, Shri J. Ramapathi
 Rao, Shri Thirumala
 Rao, Dr. V. K. R. V.
 Raut, Shri Bhola
 Reddi, Shri G. S.
 Reddy, Shri P. Antony
 Reddy, Shri R. D.
 Rohatgi, Shrimati Sushila
 Roy, Shri Bishwanath
 Roy, Shrimati Uma
 Sadhu Ram, Shri
 Saha, Dr. S. K.
 Saigal, Shri A. S.
 Salve, Shri N. K. P.
 Sanghi, Shri N. K.
 Sanji Rupji, Shri
 Sankata Prasad, Dr.
 Sant Bux Singh, Shri

Santosham, Dr. M.
 Sapre, Shrimati Tara
 Sarma, Shri A. T.
 Savitri Shyam, Shrimati
 Sayeed, Shri P. M.
 Sayyad Ali, Shri
 Sen, Shri Dwaipayan
 Sen, Shri P. G.
 Sethi, Shri P. C.
 Sethuraman, Shri N.
 Shambhu Nath, Shri
 Shankaranand, Shri B.
 Sharma, Shri Naval Kishore
 Sharma, Shri Ram Avtar
 Sheo Narain, Shri
 Sher Singh, Shri
 Shiv Chandika Prasad, Shri
 Shivappa, Shri N.
 Shukla, Shri S. N.
 Shukla, Shri Vidya Charan
 Siddayya, Shri
 Siddheshwar Prasad, Shri
 Singh, Shri D. N.
 Singh, Shri D. V.
 Sinha, Shri Mudrika
 Sinha, Shri R. K.
 Sinha, Shri Satya Narayan
 Snatak, Shri Nar Deo
 Soman, Shri N. K.
 Sonar, Dr. A. G.
 Sonavane, Shri
 Sudarsanam, Shri M.
 Supakar, Shri Sradhakar
 Sursingh, Shri
 Suryanarayana, Shri K.
 Swaran Singh, Shri
 Swell, Shri
 Tarodekar, Shri V. B.
 Tiwary, Shri D. N.
 Tiwary, Shri K. N.
 Tula Ram, Shri
 Uikey, Shri M. G.
 Veerappa, Shri Ramachandra
 Venkatasubbaiah, Shri P.
 Verma, Shri Balgovind
 Verma, Shri Prem Chand
 Virbhadra Singh, Shri
 Vyas, Shri Ramesh Chandra
 Yadab, Shri N. P.
 Yadav, Shri Chandra Jeet

NOES

Ayarwal, Shri Ram Sihgh
 Banerjee, Shri S. M.
 Behera, Shri Baidhar

Berwa, Shri Onkar Lal
 Bhagaban Das, Shri
 Bharti, Shri Maharaj Singh

Brij Bhushan Lal, Shri
 Chakrapani, Shri C. K.
 Chandra Shekhar Singh, Shri

Dange, Shri S.A.
 * Das, Shri N. T.
 Fernandes, Shri George
 Ghosh, Shri Ganesh
 Gopalan, Shrimati Suseela
 Goyal, Shri Sri Chand
 Guha, Shri Samar
 Gupta, Shri Indrajit
 Haridar, Shri K.
 Jai Singh, Shri
 Janardhanan, Shri C.
 Jha, Shri Bhogendra
 Jha, Shri Shiva Chandra
 Joshi, Shri Jagannath Rao
 Joshi, Shri S. M.
 Kachwai, Shri Hukam Chand
 Kapoor, Shri Lakhan Lal

Krishna, Shri S. M.
 Kundu, Shri S.
 Lakkappa, Shri K.
 Limaye, Shri Madhu
 *Majhi, Shri Mahendra
 Mangalathumadam, Shri
 Menon, Shri Vishwanatha
 Misra, Shri Janeshwar
 Modak, Shri B. K.
 Mohan Swarup, Shri
 Molahu Prasad, Shri
 Mukerjee, Shri H. N.
 Mulla, Shri A. N.
 Nair, Shri Vasudevan
 Nayanar, Shri E. K.
 Nayar, Shrimati Shakuntala
 Pandey, Shri Sarjoo
 Paswan, Shri Kedar

Patel, Shri J. H.
 Ramani, Shri K.
 Ray, Shri Rabi
 Reddy, Shri Eswara
 Sambhali, Shri Ishaq
 Satya Narain Singh, Shri
 Sen, Dr. Ranen
 Shah, Shri T. P.
 Sharma, Shri Beni Shanker
 Sharma, Shri Narain Swarup
 Sharma, Shri Yajna Datt
 Sharma, Shri Yogendra
 Shastri, Shri Ramavatar
 Shastri, Shri Sheopujan
 Suraj Bhan, Shri
 Umanath, Shri
 Vajpayee, Shri Atal Bihari
 Yadav, Shri Ram Sewak

MR. CHAIRMAN: The result of the division is: Ayes: 220; Noes: 62.

in any Ministry, it finds it an excuse and promulgates an Ordinance.

The motion was adopted.

SHRI RAGHU RAMAIAH: I introduce the Bill.

15.13 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE: INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ORDINANCE 1969; AND INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur) : I beg to move the following:

"This House disapproves of the Indian Railways (Amendment) Ordinance, 1969 (Ordinance No. 3 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 4th June, 1969".

I deprecate the tendency of this Government to govern by ordinances. This Government has a penchant for issuing ordinances. Whenever it wants to do a thing

Actually, during this interregnum, a number of ordinances have been promulgated, most of which could have been avoided. It would almost appear that we are living in a regime of ordinances, and that consequently this august House is intended only to rubber-stamp the decisions of this Government. The latest Ordinance promulgated only 40 hours before Parliament was scheduled to meet nationalising banks is an affront to the dignity and authority of this House. There was no emergency and no immediate necessity. This ordinance nationalising banks would have deleterious effects upon economic growth. International opinion has also adversely reacted to it.

I would now come to the Ordinance in question. I would draw attention to article 123 of the Constitution.

"If at any time, except when both Houses of Parliament are in session, the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take

* Wrongly voted for 'NOES'

† The following Members also recorded their votes:

AYES: Sarvashri C. C. Desai; Meetha Lal Meena: N. T. Das and Mahendra Majhi.

NOES : Sarvashri Mohammed Ismail, P. C. Adichan, M. H. Gowda. and S. S. Kothari.